भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2989

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2024

बैगा जनजाति के लिए पहल

2989. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति के लिए क्या पहल की गई है;

(ख) मध्य प्रदेश में पीवीटीजी श्रेणी में बैगा आदिवासी लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) मध्य प्रदेश के कितने जिले अब तक बैगा विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आ चुके हैं और शेष जिलों के लिए इसका गठन कब तक होने की संभावना है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क): मध्य प्रदेश में बैगा पीवीटीजी सहित 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, माननीय प्रधानमंत्री ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का शुभारंभ किया था। इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क और दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुँच जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को 9-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य में अभियान योजना के तहत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक दिए गए लाभों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): जनगणना 2011 के अनुसार, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की जनसंख्या 414526 है।

(ग): राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में स्थापित बैगा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 6 जिले, अर्थात् डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर आते हैं। ये वे जिले हैं जहाँ बैगा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अन्य जिलों में बैगा विकास प्राधिकरण का विस्तार बैगा जनसंख्या, उनके मुद्दों और आवश्यकताओं के विश्लेषण पर निर्भर करता है।

अनुलग्नक-I

"बैगा जनजाति के लिए पहल" के संबंध में डॉ. राजेश मिश्रा द्वारा दिनांक 12.12.2024 को उठाए गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2989 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

मध्य प्रदेश में पीएम जनमन के तहत दिए गए लाभों का विवरण (21.11.2024 तक)

मंत्रालय	उपाय	स्वीकृतियां	वित्तीय स्वीकृतियां (करोड़ रुपए में)
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकान	154153 मकान	1575.11
	संपर्क सड़कें	1096.015 किमी सड़क	836.21
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप से जलापूर्ति	1310 गांव संतृप्त	उपलब्ध नहीं है
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	सचल चिकित्सा इकाइयां (एमएमयू)	74 एमएमयू स्वीकृत	25.07
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी)	572 आंगनवाड़ी केंद्र	111.24
शिक्षा मंत्रालय	छात्रावास	51 छात्रावास	117.3
विद्युत मंत्रालय	आवासों (घरों) का विद्युतीकरण	29290 आवास	143.39
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	आवासों (घरों) का विद्युतीकरण	2060 आवास	10.3
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय	मोबाइल टावर	102 बस्तियां	18.9
जनजातीय कार्य मंत्रालय	बहुउद्देशीय केंद्र (एमपीसी)	125 एमपीसी	25.99
	वीडीवीके की स्थापना	83 वीडीवीके	2.58

*संबंधित मंत्रालयों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

*****